

आन्ध्र में और दूसरे सूबों में हो रहा है यह उसी साजिश का नतीजा है (व्यवधान)...

श्री उपसभापति : ठीक है, बंट जाइये आप । (व्यवधान)

SHRI. SURESH KALMADI: Top senior officials have been sent to Karnataka to destabilise that Government. Rs. 25! lakhs are being given to MLAs. The Congress (I) is creating law and order situation in Bijapur district and the police had to resort to firing. I want to bring to the notice of this august House... (Interruptions). I want to inform this House that Congress (I) is trying to create communal troubles in Karnataka and Andhra Pradesh. After Jammu and Kashmir, they are now active in Karnataka and Andhra Pradesh. (Interruptions).

MR. DEPUTY CHAIRMAN: First hear me. I cannot allow any debate at this stage... (Interruptions).

SHRIMATI MONIKA DAS (Karnataka) : This is a serious matter. We want to discuss it... (Interruptions).

MR. DEPUTY CHAIRMAN: If both sides want a discussion on any matter, I can allow a discussion... (Interruptions). Now this matter is over... (Interruptions). You said something and they said something. How, let us proceed with the business... (Interruptions). If you want a discussion on any matter, please give me notice. I will consider it... (Interruptions)

SHRI SURESH KALMADI: We want to call Attention on this toppling game in Karnataka... (Interruptions)

SHRIMATI MONIKA DAS: We also want to discuss it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mrs. Monika Das, I cannot allow any discussion now. We will discuss Karnataka, when the time comes to discuss, it.

Now Calling Attention. Shri Kailash; Pati Mishra.

Calling Attention to a matter of Urgent Public Importance

Situation arising out of Reported movement of extremists to establish an independent 'Kolhan Nation' in Chaibasa Region of Singhbhum District in Bihar

श्री कैलाशपति मिश्र (बिहार) : श्रीमान, बिहार के सिंहभूम जिले के चाइबासा क्षेत्र में एक स्वतंत्र 'कोल्हन राष्ट्र' की स्थापना के लिए उग्रवादियों के कथित आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति और इस मामले में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की ओर मैं गृह मंत्री का ध्यान दिलाता हूँ ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRIMATI RAM DULARI SINHA): Sir, areas covering Chaib. "Sadar, excluding Chaibasa town and Chakradharpur sub-division of Singhbhum 3 district is called Kolhan area.

श्री हुस्मदेव नारायण यादव (बिहार): मेरा एक प्वाइंट ऑफ आर्डर है । मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मंत्री महोदय सदन में जो बयान दे रहे हैं उस की हिन्दी की प्रति नहीं आयी है और जब तक हिन्दी की प्रति हम को उपलब्ध न करायी जाय तब तक इस स्टेटमेंट को रोका जाय क्योंकि यह संविधान और भाषा फार्मुला के विपरीत है । सदन में हिन्दी और अंग्रेजी की प्रति साथ साथ आनी चाहिए । जब तक हिन्दी की प्रति उपलब्ध न हो तब तक इस कार्यवाही को रोका जाय और हम को हिन्दी की प्रति पहले दिलायी जाये तब यह कार्यवाही आगे चले ।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : माननीय सदस्य के पास मर्णन है। इस का अनुवाद वे हिन्दी में सुन सकते हैं।

श्री उन्समापति : यह ठीक है, लेकिन आप इस का ध्यान रखें कि जब इस तरफ आप वयान दें तो अंग्रेजी के साथ साथ हिन्दी की प्रति भी सदस्यों उपलब्ध करायी जाये।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : आगे से ध्यान रखूंगी।

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE); Sir, let the Hindi version come and, in the meantime, let the discussion continue. In future, this sort of thing should be avoided.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes.

SHRIMATI RAM DULARI SINHA: S^.....

In Kolhao area an organisation called Kolhan Raksha Sangh was formed in October, 1978. The Sangh has been demanding independence of Kolhan tribal belt covering about 1400 villages in Singhbhum district. The Sangh claims that the area which was governed by "Wilkinson's Rules" of 1837 under which all the Executive, Judicial, Revenue and Police powers are vested in tribal village functionaries like Mankis and Mumgas gives them a measure of autonomy.

2. Shri Narayan Janko is reported to be the President. Shri Krishan Chander Hembram the General Secretary and Shri Christ Anand Topno the legal advisor of the Sangh.

3. In 1980-81 Kolhan Raksha Sangh started an agitation for felling valuable forests in Singhbhum district. They have

been attacking and even killing adivasis who do not support their demand for a separate Kolhan State. During last 8 months the Sangh is reported to have killed 17 and abducted 49 persons.

4. According to reports, Shri Narayan Jonko and Shri Christ Anand Topno visited London and Geneva in September, 1981. During these visits, they submitted memoranda to the British Government and the United Nations Office demanding independent status for 'Kolhan Government' and membership of U.N. The Sangh also submitted a memorandum in November, 1983 to the Chairman of the CHOGM held at New Delhi requesting ratification of Kolhan Government.

5. The Government is vigilant about the activities of the Sangh and necessary steps have been taken to deal with the situation. Prosecutions have been launched against 16 members of the Sangh by the Bihar Police for offence of sedition under Section 124A and 120-B of I.P.C.

6. The law and order enforcement machinery in the area has been strengthened. Development activities have been intensified in the area particularly for providing drinking water, primary education, medical and fair price shop facilities. It may be mentioned that the Special Central Assistance for supplementing the programmes of Bihar Government has been increased from Rs 15.66 crores in 1983-84 to Rs. 18.23 crores in 1984-85. The Government of Bihar is taking steps for greater participation of the tribals in the local administration both in the developmental and regulatory spheres. In order to prevent illegal felling of forests, armed pickets with magistrates have been stationed at sensitive pockets. The local administration has been instructed to look into the grievances of the people and take immediate remedial steps for redressal of the same.

7. The Government is fully seized of the situation and efforts are being made to create a climate of harmony and accelerate the pace of development in the area.

श्री कौलाश पति मिश्र : जनसत्तापति महोदय, सरकार का जो वक्तव्य है उसमें समस्या की गंभीरता को इस हल्के ढंग से रखने की कोशिश की गई है कि जिससे यह दिखाई दे रहा है कि सरकार मूल समस्या को समझ नहीं रही है। यह कोल्हन राष्ट्र की घोषणा किस आधार पर हुई पहले तो इसे समझने की आवश्यकता है। सिंहभूम के अंतर्गत जो साल वृक्ष का विशाल जंगल है वह एशिया में प्रथम स्तर का जंगल माना जाता है। वन विभाग ने उसे 6 टिक्केजनों के अंतर्गत विभाजित करके सारणा, चाई बासा, नार्थ, चाईबासा साउथ, पोरहाट, दालभम तथा कोलाहान में रखा है। कोलाहान जंगल इतना घना है, इतनी बड़ी प्रापटी है राष्ट्र की जिसके लिए देश को बड़ा गौरव है। लेकिन यह भी सत्य है कि वहां का रहने वाला मूल निवासी आदिवासी है जो कि 38 वर्षों की आजादी के बाद भी आजादी की एक किरण भी उनको देखने को नहीं मिली। जंगल में जाने के लिए पक्की सड़कें नहीं हैं, स्कूल वहां नहीं हैं, अस्पताल नहीं हैं, शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, कोई जमीन उनके जीवन में आजीविका का निर्वाह करने के लिए नहीं है। कोई साधन उपलब्ध नहीं है। यही नहीं, परंपरागत जो वनों में रहने वाले अधिकार रखते थे, वह भी उनसे छीन लिया गया है, लेकिन उनका ऐसा चरित्र है, कि वह बहुत सीधे-सादे, भोले-भाले अपनी संस्कृति के लिए बड़े कट्टर हैं, वनों के ऊपर श्रद्धा रखने वाले हैं और वृक्षों की पूजा करने वाले हैं। उनके इस भोलेपन का बहुत वर्षों से लगातार शोषण होता रहा है। सरकारी अधिकारी शोषण करते रहे, ठेकेदार करते रहे, किसी ने नहीं देखा

कि उनके जीवन में परिवर्तन आया तो क्या होगा।

इसी बीच में एक पड़यंत्र शुरू हुआ, 13-14 साल पहले दो व्यक्ति वहां पर आए। अतिसिंघस राज और मेहुअरी परंपिया नामक महिला वहां आईं जिसने अपना नाम बदलकर कुमारी ज्योत्सना रख लिया। ये दोनों आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े। प्रैमि वह लड़की केरल की रहने वाली है। लेकिन मिशनरी ऐक्टिविटीज में वह असम में आई। फिर चाईबासा पहुंची। उसके बाद ये चाईबासा रोमन कैथोलिक चर्च में आए। अतिसिंघस राज बदर बन गए और कुमारी ज्योत्सना सिस्टर बन गई। ये चर्च में रहते नहीं। वहां पहुंचकर पहला काम उन्होंने यह किया कि सिंहभूम 'एकता' साप्ताहिक अखबार निकाला। उसकी प्रति आप मंगाकर देखेंगे कि लगातार देश के खिलाफ विष बमन हो रहा है। राष्ट्र को तोड़ने, विखंडित करने की प्रवृत्ति को बढ़ाने और उनमें आग भड़काने की बातें उसमें लिखी जाती हैं। कुमारी ज्योत्सना ने वहां पर सख्ता बोड़ी पत्ता मजदूर यूनिवर्स बनाने का नाटक किया। वह बड़ी कुशल और परिपक्व है। उनके आदिवासियों की भाषा संखी, उनके रीति, रिवाज सीख लिए, नृत्य गान सीख लिये और उनके बीच में घुसना शुरू किया। जहां कहीं चर्च के स्कूल थे वहां जाकर उसने अनेक टोमें बनाया शुरू की। लोपोगुटु में इस प्रकार उनका हक अड़्डा बन गया। इसके साथ और कई टोमें बन गई। उसके बाद इन्होंने एक साथ दो काम किए। एक तो जो वहां की राष्ट्रीय सम्पत्ति है, जो साल वृक्ष का जंगल है, जिनको मेचोई होने में कम से कम 80 साल लग जाते हैं, इस घने जंगल

[श्री कैलाश पति मिश्र]

को कटाई का अभियान शुरू किया। देश को इतनी बड़ी संपत्ति की सफाई शुरू कर दी। सरकार को अभी तक यह मालूम नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके पास कोई ठोस आंकड़े हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ उन्होंने जानकारी दी है कि उस जंगल के अन्दर 18 से 20 हजार एकड़ के जंगल को पूरी सफाई हो गई है।

जहाँ तक सरकारी अधिकारियों का नवाल है, कोई स्कूल का टीचर हो, कोई अस्पताल का डाक्टर हो, कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अफसर हो, कोई रिलीफ आफिसर हो, उसकी हिम्मत नहीं है कि वह जंगल में रहे। सब चाईवासा में आकर डेरा डाले हुए हैं। हिम्मत नहीं होती कि अंदर जाए। वहाँ कई घटनाएँ हुई और उसमें कड़ियों की हत्याएँ हुई, लोगों को जला दिया गया। अब तमाशा शुरू हुआ कि ग्राम रक्षा दल की स्थापना की गई। हथियार भरने शुरू किये हैम्बरनम के नेतृत्व में, सरकार ने और चीजों का नाम भी लिया है। उनके नेतृत्व में उग्र आन्दोलन शुरू किया। गांव के भोले-भाले आदिवासी अगर उनकी पहुंच में नहीं जाते तो उनकी हत्या कर दी जाती है। एक-एक गांव में 20-20, 25-25 की हत्या हो रही है। गत वर्ष की ही घटना है कि एक स्थान पर 13, एक गांव में 6 जो कि उनके कब्जे में जाने को तैयार नहीं थे तो उनको पकड़ लिया गया और टुकड़े-टुकड़े में शरीर काट दिया गया। काट कर नदी में लाकर फेंक दिया। खबर सरकार को मिली और बड़ी सूझ-बूझ के साथ पुलिस गई। सूझबूझ के साथ जो पुलिस गई वह न लाश पकड़ पाई और न लाश के टुकड़े को पकड़ पाई और

न ही कोई हथियार अपने कब्जे में लिये। जुलाई महीने की घटना है चाईवासा से चालीस किलोमीटर दूर भभरिया गांव है और उसके बगल में चार किलोमीटर दूर अप्रैल महीने में भी एक घटना घटी। 6 निर्दोष को पकड़ा गया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिये गये और उसको फेंक दिया गया। भभरिया हैम्बरनम के जैसा गांव नहीं है 19 जुलाई की सुबह भभरिया पोल की नौद टूटती है तो देखने हैं कि भभरिया गांव को दस हजार लोगों ने हलके हथियारों के साथ घेर लिया है। अप्रैल महीने में जो 6 की हत्या की घटना हुई थी सरकार हत्या करने वालों में से किसी को नहीं पकड़ पाई लेकिन एक बी एम पी की टुकड़ी भेजी गई। उनको पता लग गया कि भभरिया वाले विरे हुए हैं, बी एम पी जवान उन को हटाने में सफल नहीं हो रहे थे तो फायरिंग होने लगी और बाद में मरने-कटने की घटना घटी हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस (आई) के ही एक लोक सभा के सदस्य हैं बाबू सुमराय व उनकी पत्नी कुछ साल पहले देश को दुबैल बनाने वाले, देश को टुकड़े करने वाले उग्र-वादियों के द्वारा पकड़ लिये गये थे। वह एक बड़े नामी हैं, ख्याति प्राप्त हैं, बड़ी उनकी तूती बोलती है। तीन दिनों तक कांग्रेस संसद बाबू सुमराय और उनकी पत्नी समृति सुमराय मर गई या जिंदा है यह पता नहीं लग रहा था। जब बाहर से बी आई पी होने के कारण भारी फोर्स पहुंची तो फोर्स को भी अनुभव, प्रार्थना करनी पड़ी। तब जाकर किसी प्रकार से उनकी जान बची। उनकी घड़ी हाथ से निकल गई थी। लगातार यह हालत दिखाई दे रही है। वहाँ पर भारत सरकार या विहार सरकार कोई हल निकालने के लिये दिखाई नहीं दे रही है। मैं निरीक्षण

लिया था। एक स्थान पर जा रहा था अचानक देखा कि तीन मौ के लगभग लोग जंगल काटने में लगे हुए हैं। घड़-बड़ाहट मुझे भी हुई। मेरे साथ जीप पर जो ड्राइवर बैठा था वह भी नरक्स हो गया था। जब मुझे पता लगा कि वह नरक्स हो गया तो मैंने उससे कहा उधर मत देखो। संयोग की बात है कि वे जंगल काटने में लगे हुए थे वे हमारी तरफ देख न पाये और हम निकल आए। लेकिन जगह-जगह भय और आतंक का एक साम्राज्य दिखाई दे रहा था। आश्चर्य यह हो रहा है कि जाईवासा के सिधमूम एकता आगे बढ़ रहा है, उसकी पूरी टीम काम कर रही है। दूसरी ओर यह एक केन्द्र बन गया है। जी एल चर्चा रांची से लावों की मात्रा में विप्ले पम्फलेट चलते हैं। पूरे जंगल में लगातार भरे रहते हैं। अवस्था यहां तक ही नहीं है वलिक कोलाहन राष्ट्र की घोषणा उन्होंने की है। उस घोषणा के पीछे सशस्त्र क्रांति का उन्होंने आवाहन किया है। मैं सरकार को सूचित करना चाहता हूं कि उसी भवरिया गांव की बगल में एक मंजारी बस्ती है। अगर आप में हिम्मत है तो आप उस गांव में खच कराइये। अच्छे से अच्छे सो फिस्टिकेटड आर्म्स वहां पर एक नहीं मैकडों की तादाद में भरे पड़े हैं। सरकार वहां पर पहुंच नहीं पा रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर सरकार ने इसका कोई रास्ता नहीं निकला तो स्थिति खतरनाक हो जाएगी। मैं इस पक्ष का भी नहीं हूं कि आप केवल मिलिटरी से इस समस्या को हल करने की कोशिश करें। ये आदिवासी कौन हैं? ये हमारे ही देश के निवासी हैं। ये विदेशी नहीं हैं। ये हमारे ही खून के लोग हैं। हमें उनकी जिन्दगी में विश्वास पैदा करना होगा। उनके

जीवन का उत्थान करना होगा। वहां पर सड़कें बनानी होंगी, स्कूल खोलने होंगे और उन्हें पेट भरने के लिए आश्वासन करना होगा। उनके हाथ में काम देना होगा। उन्हें अपने जीविका पार्जन के लिए काम-धन्दा देना होगा। अगर सरकार ने इन लोगों के उत्थान के लिए कोई अच्छी योजना बनाकर नहीं रखी तो नतीजा यह होगा कि अभी तो उनका संबंध केवल देशी लोगों के साथ ही है, लेकिन अब देखने में यह आ रहा है कि विदेशियों से भी उनका संबंध आ रहा है। मैं एक छोटा सा कोटेशन पढ़कर सुना देना चाहता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर यह ध्यानापूर्ण प्रस्ताव इस सदन में मंजूर नहीं होता तो न तो इस सदन को इस समस्या के बारे में पता चलता और न ही देश को पता चलता। यह मैं 'स्टेट्समेन' अखबार का समाचार पढ़ रहा हूं, किसी अन्य समाचार पत्र का नहीं पढ़ रहा हूं —

"In December, 1981, leaders of 42 Commonwealth countries received copies of a confused letter addressed in London from the Government of Kolhan, Indian sub-continent, seeking help to sever from India."

ऐसी खतरनाक स्थिति वहां पर पैदा हो गई है। बहुत बड़े पैमाने पर यह समस्या पैदा हो गई है। यदि भारत सरकार ने और बिहार सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिए कदम नहीं उठाये, इस समस्या को सुलझाने का प्रयास नहीं किया तो ये उपद्रवी जंगलों को काटने चले जाएंगे राष्ट्रीय सम्पत्ति का सत्यानाश करते चले जाएंगे। दूसरी ओर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ये आदिवासी हमारे ही रक्त के लोग हैं। ये गरीबी के

[श्री कैलाशपति मिश्र]
घिरे हुए हैं। उन्हें ऊपर उठाने के लिए तत्काल कदम उठाये जाने चाहिए। मैं चाहता हूँ कि सरकार शीघ्र वहाँ पहुँचे, विदेशियों का प्रभाव वहाँ से समाप्त करे और वहाँ पर जो विदेशी मिशनरीज हैं उनको वहाँ से बाहर भेजा जाय।

SHRI BISWA GOSWAMI (Assam):
Mr. Deputy Chairman, Sir, the statement of the hon. Minister is very unsatisfactory. It seems that the Government of India has not understood the gravity of the situation.

Sir, it has been reported in the "News Time" of 23rd July last that even the Minister of State for Home Affairs, when contacted by one correspondent, expressed her ignorance about the things going on in the Kolhan area. Sir, this situation has arisen as a result of total neglect of the backward tribal people of that area. Sir, it has been our experience that the Government is unsympathetic towards the legitimate grievances of the people living in remote areas. And as a result of that, these people have felt neglected and they have started this separatist movement. Sir, the tribal people of Kolhan area claim themselves as citizens of an independent Kolhan State and they have formed their own Government. The Kolhan movement was formerly started in December, 1982 when the supporters of the movement announced the formation of a self-styled Government of Kolhan under the British Commonwealth. Mr. Narayan Jonko was the Chief of the Government, and Mr. Christ Anand Topno was in charge of foreign affairs and its chief legal advisor.

MR. DEPUTY CHAIRMAN. That is already in the statement.

SHRI BISWA GOSWAMI: The main argument of the Kolhan freedom leaders is that they are not part of the independent country.

Became they say that area was not covered by the Transfer of Power of 1947, and they have taken recourse to the Wilkinson Rule of 1836. What is surprising, Sir, is that even after 37 years of independence nothing has been done by the Government to do away with this rule. Even today the tribals feel that they are ruled by the Wilkinson rule. The Panchayati raj system has not been extended to that area and they are, therefore, feeling that they have reasons to believe that they still continue to be ruled by this rule. Sir, they have claimed for themselves a separate identity. Sir, I doubt that taking advantage of the backwardness of the area and the poverty and ignorance of the people; the tribal people, there may be some agents or some agencies which are trying to exploit the situation. I want to know from the hon. Home Minister whether the Christian missionaries have got a hand in instigating the tribal people there and also I want to know what concrete steps the Government will take to win over the people of that area because simply by sending the military or the police there the problem cannot be solved. (Time bell rings). And, unless and until the hearts of the people of that area are won over by adopting certain steps and measures for the improvement of that area and removing the legitimate grievances of the people you cannot win them over. Simply by sending the military and the police the situation can not be controlled. As a matter of fact, the police have been sent and there have been cases of firing on several occasions. In fact, in some places even the policemen do not dare to enter the places of Kolhan area. Therefore, Sir, it is highly necessary that Government take urgent measures to win over the people of that area and take steps for the improvement of the tribal people.

श्री राम चन्द्र भारद्वाज (बिहार) :
मान्यवर, अभी मंत्री जी के वक्तव्य और अपने मित्रों को सुनने के बाद मुझे लगा कि वस्तु स्थिति से अभी तक हम दूर हैं। क्योंकि अगर कोल्हन का संबंध इस चीज से हो कि ट्राइबल्स को कुछ नहीं मिलता है, उनके समक्ष अभाव का वातावरण है और इसकी

बजह से इतना बड़ा उत्साह हो रहा है, ऐसा मानने में कठिनाई का अनुभव में करता हूँ। बड़ी लम्बी कहानी 1936-37 से लेकर आज तक की है। माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि अभी पिछले आठ महीनों में 17 हत्याएँ हुईं। मान्यवर, उन्हें याद होगा, वे जानती होंगी कि 25 अगस्त का जब एक हाट पर आका पड़ा और जिसमें 13 आदमी गायब हुए उनमें 12 लाशों का पता नहीं चला। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि पिछले 8 महीनों में 17 और इसके पहले 13 जो हाट से गायब हुए और 12 हत्याएँ हुई, जिनकी लाशें नहीं मिलीं, इन सब को मिला कर इस बीच की क्या किम्वदंती है, जितनी भी हत्याओं के बारे में जो जानकारी है। मान्यवर, यहाँ सारी बातें कही गई हैं और यह भी कहा गया है जो इसके नेता और अभी हमारे विश्वास गोस्वामी जी ने पूछा कि क्या इसमें फारेन मिशनरीज का हाथ है, तो वे इस सब को बहुत दूर तक ले गये हैं। मैं जो स्थिति समझता हूँ वह यह है कि इसके दो प्रमुख कारण हैं, एक आर्थिक और दूसरा राजनैतिक। राजनैतिक मैं इसलिये कह रहा हूँ मान्यवर, कि अभी तो उसे कोल्हनस्तान की संज्ञा दी जाती और सभी वे इसे कोल्हन देशम की संज्ञा देते हैं। तो यह खालिस्तान और तेलुगू देशम से मिलता-जुलता हुआ एक शब्द है। कहीं से उनके मन में रीजनलिज्म का भाव पैदा हुआ या किया गया और उसके बाद स्वतन्त्र सत्ता के लिये उन्होंने कोल्हनस्तान या कोल्हन देशम को स्वीकार करने की बात सोची। आज वे यहाँ तक पहुँच गये हैं कि स्वतन्त्र देश की बात नहीं करते हैं यह बात सही है उनका रवैया भी संभव में नहीं आता वह डाक्टर रिबोल्टी से जाकर व्हाइट हाल में मिले लंदन के अन्दर वहाँ जाकर एक मेमोरैंडम दिया कि वह कामन्वेल्थ से माइड होते हैं इसलिये कामन्वेल्थ के सदस्य हैं वहाँ पर डाक्टर रिबोल्टी ने यह आश्वासन दिया कि आपका इंग्लैंड में स्वागत है और आप यहाँ आ सकते हैं इस

पर बात कर सकते हैं। इनके प्रतिनिधि जेनेवा गये और उन्होंने समझाया कि कामन्वेल्थ के सदस्य हैं, उन्हें मान्यता मिलनी चाहिये, कामन्वेल्थ के प्रतिनिधियों की एक कॉन्फ्रेंस कोल्हनस्तान कोल्हन देशम में होनी चाहिये जिसने यह सारी बातें साफ हो जाएं। इनको क्या आश्वासन मिला मैं नहीं जानता मगर इतना जानता हूँ कि वहाँ से जब लौट करके आये तो 'चोगम' के समय भी उन्होंने इस तरीके की बात कही कि उनका राष्ट्र एक स्वतन्त्र राष्ट्र है जिसका एंटी-सेन्सिबल ब्राउन है। उन्होंने अपने यहाँ घोषणा की कि हम यूनिवर्सिटी भी बनायेंगे और उसका एफिलियेशन आक्सफोर्ड से करायेंगे। ये सारी घोषणाएँ उन्होंने अपने यहाँ की। मान्यवर, जब वे आए तो वे रोडीशन के चार्ज में बन्द कर दिये गये। जिसको उनका आमी चोक कहा जाता है, कि मुन्ते हैं कि वे सहारा के जंगलों में बैठ गये हैं वहाँ से आश्रित कर रहे हैं जिनको पकड़ा नहीं जा सका है। बाकी इलाहाबाद और दूसरी जेलों में हैं। उनकी मांग यह है कि हमने स्टेट कहां मांगा था, हमने स्वतन्त्र राष्ट्र कहां मांगा था, हम तो स्वतन्त्र राज्य चाहते हैं। तो अब यह बंटवारा राज्यों में, बिहार के अन्दर जो राज्य हैं, वहाँ पर उनकी मांग उतर कर आई है। सही बात यह है कि उसका समर्थन वहाँ की जनता द्वारा उनको प्राप्त नहीं है और जब समर्थन प्राप्त नहीं है तो वहाँ की जनता के भी दागो है। आदिम जाति और आदिवासियों के भी विरोधी हैं, जो इसको नहीं मानते। अर्थ यह है कि न उस भूमि से उनको प्यार है और न उस भूमि के लोगों से उनको प्यार है न कोई स्वतन्त्रता की बात वे उनके लिये करना चाहते हैं। वे कहीं से कठमुतली की तरह से डोर खींचा जा रही है और वह भाँच रही है। उसका मुख्य कारण यह है डा० रामन्ना के अनुसार जो अभी छानबीन हुई है 73 हजार टन यूरेनियम सिर्फ कोल्हन, राजस्थान के उस क्षेत्र में अभी तक मिल

[श्री रामचन्द्र भारद्वाज]

गया है और उसकी जानकारी प्राप्त हो गई है भविष्य में आगे भी जानकारी प्राप्त होगी और इसकी खाने मिलेगी, मिलने की अभी भी आशा व्यक्त की गई है। जैसे कि माननीय कैबिनेट मिश्र जी ने भी कहा कि सहारा साल जंगल एशिया का सबसे बड़े जंगल है। वहाँ पर कोकिंग कोल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, थिरेनियम का जहाँ तक सवाल है वह उपलब्ध है, यूरेनियम की बात बहुत पुरानी चल रही है। यूरेनियम एटोमिक एनर्जी के लिए एक आवश्यक कपोनेट है। उसके लिए बहुत दिनों से वहाँ लड़ाई चल रही है। इसके लिए कई एडिटर मारे गये। 'नया रास्ता' के एडिटर रोबोल का मर्डर हुआ। इन्फोफ़्रॉन्ट से 10-12 साल पहले बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उसकी जांच का भार मुझे दिया था और मैंने उसकी जांच रिपोर्ट बिहार कांग्रेस कमेटी के माध्यम से तत्कालीन गृह मंत्री श्री उमाशंकर दीक्षित को समर्पित किया था। सदनों में भी इसकी चर्चा चली थी और दूसरे सभी अखबारों ने उस पर सम्पादकीय टिप्पणी भी लिखी मगर उस समय सरकार को यह मानने में कठिनाई हो रही थी, कि यूरेनियम स्मगल हो सकता है, मगर जो वहाँ यूरेनियम स्मगल हो कर गया और उसका टेस्ट हुआ और माना गया कि यह यूरेनियम सबसे अच्छा है इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है तथा उस क्षेत्र को किस तरह से उपेक्षा की गई..... जिससे कि इस मामले में सेल्फ सफ़ीशियंट नहीं हो सके। मान्यवर, ऐसा माना जाता है कि सारी दुनिया में जो कोल्हान का क्षेत्र है वह सर्वाधिक सम्पन्न क्षेत्र है, उसके समान सम्पन्न क्षेत्र कोई नहीं है और जितने प्रकार के खनिज पदार्थ एक साथ वहाँ उपलब्ध हैं

वे कहीं और नहीं हैं। तो इस पर सारी दुनिया की नजर है और खास तौर से उन राष्ट्रों की अवश्य है जो हमें कमजोर करना चाहते हैं। 16 जुलाई के "स्टैट्समैन" में इस तरह की एक टिप्पणी भी आई है जिसमें कहा गया है कि वहाँ जो उनकी टीम गयी तो कहा गया कि जिस तरह से खालिस्तान मूवमेंट में बाहरी हाथ है, विदेशी हाथ तो उसी तरह से यहाँ के मूवमेंट में भी विदेशी हाथ है। यह बाद सही है कि वहाँ के लोग बड़ी गरीबी की स्थिति में हैं उसका कारण, सरकार ने उनको गरीब रखा है ऐसी कोई बात नहीं है। उसका कारण यह है कि वहाँ टोटल एक्सप्लायटेशन आफ द रिसोर्सेज नहीं हो पाया है, प्रापर डेवलपमेंट आफ द एरिया नहीं हो पाया है और ऐसे क्षेत्र जो बराबर से उपेक्षित रहे हों उनका एकाएक विकास कर देना भी किसी सरकार के लिए संभव नहीं होता। मगर ऐसे मामलों से इन हत्याओं से ऐसी बारदातों से तेलगू देशम की तरह अथवा खालिस्तान की तरह कोल्हान या कोल्हान देशम की माँग को दबाने के लिए दो चार लोग जो बहके हुए हैं वे अगर जेल में रहते हैं तो उसे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि विचार जो है वह फैलता है, मनुष्य बंद हो जाता है विचार कभी कठघरे में बंद नहीं होता उस विचार को बंद करने के लिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वहाँ के लोगों को जो कुछ चाहिए वह मुहैया कराये। मगर मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने अभी तक वह कदम नहीं उठाये हैं जो वहाँ के आंदोलन को समाप्त करने के लिए उठाने चाहिए। संभवतः सरकार ने इसको महत्व नहीं दिया है अन्यथा ये सारी बारदाते नहीं होती यह मैं कहना चाहता हूँ (समय की घंटी)।

मान्यवर, एक छोटी सी बात है जो कि बहुत बड़ी भी है। वहाँ के इंस्पेक्टर आफ पुलिस ने 25 अगस्त 1981 को एक एफ० आई० आर० दिया था जिसमें उन्होंने पूरी कहानी लिखी थी कि यहाँ यह हो रहा है, ऐसा-ऐसा उत्पात हो रहा है, ऐसी ऐसी संभावनाएँ हैं, इसकी परिणति खतरनाक हो सकती है और इसमें जल्दी से जल्दी कुछ होना चाहिए। यह उसका आशय था चूंकि वह एफ० आई० आर० बहुत लम्बी है इसलिए मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूँ कि 16 जुलाई के "स्टैंडसमैन" में लिखा है कि जो टोस गयी थी उसने एफ० आई० आर० की कापी लेकर इसको पब्लिश किया है। इसकी ओर मैं ध्यान आकर्षित करूँगा और यह जानना चाहता हूँ कि जब 25 अगस्त को वहाँ के पुलिस अधिकारी ने इस प्रकार एफ० आई० आर० लाज किया तो 25 अगस्त, 1981 से लेकर आज तक सरकार ने क्या कदम उठाये हैं जिसकी वजह से यह कदम आगे नहीं बढ़ता और इसमें रोकथाम की जा सकती तथा जो बाहरी और विदेशी या भोतर की ध्वंसात्मक ताकतें हैं उनसे बचा जा सकता है।

SHRI BADRI NARAYAN PRADHAN (West Bengal): Mr. Deputy Chairman, Sir, I have read the statement made by the hon. Minister CQ this 'Kolhan Nation' problem, I have also heard the speeches of friends here. This problem is there throughout India. You know about the revolt of the Nagas. There is also the Mizo problem. The same problem is there in the North-East from where I come; among the Nepalis, there are Gorkhas. In West Bengal there is Jharkhand Mukti Morcha. In the North there is Uttarakhand Pradesh. These are the demands of these people and their demands are being aided by foreigners. In Darjeeling there are Prantiya Parishad and Gorkha National Front who are demanding a separate district for Gorkhas and Nepalis. There was firing in these areas and two people died last year. So, these people

are there and they are being supported by the Congress(I) Party. Jharkhand Mukti Morcha is being supported by Congress (I). The reason is that the Congress (I) party is against the Left Front Government of West Bengal, in Tripura the Government is very much anxious to safeguard the interest of the tribal people over there. It has created the Tribal Development National Council, but the tribals over there are not satisfied. They are revolting against the government and the Congress (I) is supporting these people. Like the 'Kolhan' demand, in Jharkhand, in Tripura and in whole of the North East region these demands are coming up. So, this is the policy of the Government. Apart from the support from the Congress (I), they are getting the support of the missionaries. These people are uneducated illiterate. They are being incited. Otherwise, they are unable to do anything on their own.

I would therefore request the Treasury Benches to be vigilant and to do the things that are required to be done for the tribal people, so that they may not fall a victim to the foreign people.

* This is all that I want to say.

श्री हुकमदेव नारायण यादव : उप-सभापति महोदय, माननीय कैलाश पति मिश्र जी ने जिस समस्या को और सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है और माननीय हमारे मित्र, श्री रामचन्द्र भारद्वाज जी भी उस पर अपनी राय रख रहे थे, जो अभी समस्या है, उस समस्या का केवल एक ही रूप नहीं है। अगर उसके लिए कहा जाए कि सरकार की नीति ही जिम्मेदार है, तो सरकार की नीति के साथ साथ और बातें भी जिम्मेदार हैं। खास करके बिहार का जो दक्षिण बिहार है, उस इलाके का जो आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक स्थिति है, वह वहाँ के लोगों को दिन-प्रति-दिन मजबूर करता जा रही है कि वह किसी न किसी तरह से कोई आन्दोलन खड़ा करें और यह हालत आज से नहीं पहले से है। अगर मेरे पास समय होता, तो मैं बता देता कि

[श्री हुसमदेव नारायण यादव]

आज से ही नहीं, अंग्रेजी राज में और उससे पहले की वहाँ की स्थिति क्या कर रही है। लेकिन नये सिरे से आजाद भारत में देखें, तो उन आदिवासियों के क्षेत्रों से सा. ज. अध्याय सिंह एक बहुत बड़े नेता निकले थे और आदिवासियों के वह प्रतिनिध बन रहे थे, तो सत्ता की ओर से प्रलोभन देकर, पद और प्रतिष्ठा का लोभ देकर अध्याय सिंह को अपने में ले लिया गया। फिर आदिवासियों के अन्दर एक नेता, निकले, कई नेता निकलते गए। बागुन सम्बई I.P.M. जो इस खंड मुक्ति मोर्चा के थे जो कांग्रेस में आगे, स्वर्गीय श्री बागुन निकले थे जो बिहार विधान सभा में प्रथम बार विरोध पक्ष के नेता बने थे, उनकी भी कांग्रेस ने अपने में ले लिया। अभी श्री बागुन सारेन जो वहाँ का एक नौजवान निकला था जो लोक सभा में जीत करके आया है उन्हें भी लेने की वहाँ बात चलती है। विनोद बिहारी महर्षी कोई एक नहीं, अनेक नेता वहाँ निकलते गए, उनको कांग्रेस वालों ने अपने में मिलाने की कोशिश की उन नेताओं को मिलाने की वनिस्पत कभी भी सत्ता के जरिए कोशिश नहीं की कि वहाँ की जनता को जो कठिनाई है, उन कठिनाइयों को कैसे दूर करें। जनता की कठिनाइयों को दूर करने का तो प्रश्न नहीं रहा बल्कि उनके अन्दर से जो नेता निकले, उन्हें फुसला करके लकड़ी सुंघा करके गांव में जो लकड़ी सुंघा होता है बंध बत्तालों को लकड़ी सुंघा कर झोला में बंध कर लेता है उसी तरह कांग्रेस करती रही है। यह नीति बंद होनी चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि उत्तर बिहार के आप भी हैं उत्तर बिहार के माननीय मंत्री भी हैं राम चन्द्र भारद्वाज भी हैं, हम सब उत्तर बिहार के हैं, लेकिन गंगा के उस पार का आदिमी सबसे ज्यादा शोषक है दक्षिण बिहार का

जिसके कारण आज वहाँ के आदिवासियों की यह हालत है। गाजीपुर से, बलिया से, छपड़ा से आपके बनारस बलिया और बस्ती के जो लोग हैं जो जानते हैं धनवाद में जो बड़े हीरो समझते हैं जिन जिन का यह नाम है एक छत्र सम्राट बनाया है कहीं से कहीं चले गए। ये सब के सब जाकर उस एरिया में बैठ गए हैं और अपने डंडा के काम पर लाठी के बल पर सोटा के बल पर, उस आदिवासियों को शराब पिला देते हैं जमीन लिखा ले जाते हैं और जमीन लिखेगा एक एकड़ बेचेगा तो चढ़ा देगा उस पर 5 एकड़, उनका घर-साराडी जमीन जायदाद सब पर उस का उस चढ़ा पर कर रजिस्टर करा लेता है जब उस बेचारे का नशा टूटता है तो फिर कागज को ले करके जाता है कि हमको यह वेदखल कर रहा है, हमें इंसाफ चाहिए तो दरोगा जो पुलिस थाने में बैठा हुआ आदिमी है, वह इंसाफ नहीं देता बल्कि उन गरीबों के ऊपर डांटे मारता है और उससे भी ज्यादा उन आदिवासियों की जो लड़कियां हैं उन इलाकों में आप जाकर देखिए कि इंसान का रुह कांप उठता है या नहीं उन आदिवासियों के घर में जो लड़कियां हैं उन लड़कियों को उस इलाके में जो गैर-आदिवासी अफसर जाते हैं जिनका नाम भी लिया है जो बड़े लोग तस्कर सम्राट माफिया गिरोह के हीरों समझते हैं जो गैंग है, यह गैंग उन आदिवासियों की लड़कियों के साथ दिन दहाड़े बलात्कार करता है अपनी योन तृष्टि के लिए लड़कियों को उठा उठा कर ले आता है। इन सब बातों की प्रतिनिध्या उन आदिवासियों के अन्दर जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उन पर होती है। आजाद भारत में यह बताइये, मैं यह पूछता हूँ सरकार से, गृह मंत्री जी से बताइये कि उस आदिवासी एरिया में आज तक भी एक जज के लायक पैदा नहीं हो सका। रांची में हाई कोर्ट का एक बेंच

बनाया गया लेकिन उसमें आदिवासी कोई जज नहीं बनेगा, आदिवासी कोई सरकारी वकील नहीं बनेगा, आदिवासी कोई बड़ा अफसर नहीं बनेगा, आदिवासी कोई ऊँचे स्थान पर नहीं जायेगा। सरकार में मंत्रिमण्डल बनेगा उस मंत्रिमण्डल में आदिवासी नहीं बनेगा और कोल्हन राष्ट्र कहते हैं, इसको बनाने वाले आप ही जब केन्द्रीय मंत्रिमण्डल बनता है तो आपको ही नहीं कहता जनता पार्टी के समय में भी इस बात को लेकर मैं लड़ता था, जनता पार्टी में भी एक आदिवासी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बना, आपके वहाँ भी कोई आदिवासी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बन पाता। यही देश का दुर्भाग्य है कि देश की 14 प्रतिशत जनता जिसको आप संविधान के जरिए आरक्षण देते हैं, तोकरी के लिए 14 प्रतिशत आरक्षण देते हैं लेकिन जब मंत्रिमण्डल बनेगा तो एक भी आदिवासी कैबिनेट मिनिस्टर बनने के लायक नहीं है। कोई भी आदिवासी आदमी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लायक नहीं है, कोई उस जंगल में बसने वाला बड़े बड़े ऊँचे अफसर बनने के लायक नहीं है। जहाँ उनके राजनैतिक शोषण का सवाल है, उनका राजनैतिक शोषण हो रहा है, आर्थिक शोषण का सवाल है, मेहनत करते हैं पसीना बहाते हैं कोयला निकालते हैं जंगल काटते हैं खदान में काम करते हैं लेकिन खाने के समय भूखा पेट और तंग तन लेकर सो जाता है। उसको लूट कर कौन ले जाता है? मैं केवल सरकार को जिम्मेदार नहीं मानता भारद्वाज जी, मैंने पहले कहा चाहे वह कोई भी दल हो, लेकिन उस इलाके में लूटने वाला साफिया कांग्रेस के दल का सरदार है, वह केवल सरकार से संरक्षण नहीं पाता है, चाहे वह सरकारी दल हो कोई विरोधी दल हो उनको संरक्षण मिलता रहता है। इसलिए मैं आपसे यह प्रार्थना करते हुए अपनी बात

खत्म करना चाहूंगा कि इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। आखिरी बात अभी जंगल एरिया में रहने वाले किसान, जो जंगल में बसने वाले हैं हम अपनी जमीन में पेड़ लगाते हैं उप सभापति महोदय लेकिन जंगल के जो स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन वाले वह हैं उनका काम है। तुम अपनी जमीन का पेड़ किसी के हाथ से बेच नहीं सकते हो। सरकारी जो खरीद करने वाली एजेंसी है, उसी के हाथ तुम को पेड़ बेचना पड़ेगा। कोई भी कंपटीटर नहीं होगा। सरकार खरीदे, जो रेट तय करे, उस रेट पर आप बेचो, कहीं दस दिन में, बीस दिन में, एक महीने में, दो महीने में रुपया दोगे। हम किसान हैं, हम जमीन में पेड़ लगाते हैं, हमें बीज की आवश्यकता होती है। हम एक पेड़ काटते हैं, और बाजार से बीज खरीद कर लाते हैं। तो यह जो जंगल का शोषण, लकड़ी काटने का आदिवासियों का शोषण होता है जिन को सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। यह एक दुःखदायी है कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1981-82 में अलग राष्ट्र बनाने के लिए यह सारे पर्चे-पुर्चे दिल्ली में लेकर कहां-कहां बांटे और सरकार ने आज तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया, उनमें से किसी को पकड़ा नहीं, कोई जांच-पड़ताल नहीं की। तो सरकार कहां सोयी हुई थी, जो यह अलग राज्य बनाने के लिए यू० एन० ग्रो० में पर्चे बांटे, राष्ट्राध्यक्षों के बीच पर्चे बांटे गए और सरकार आप प्रतिबेदन देती है। तो सरकार ने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की? जो आज आतंक और अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक

[श्री हुक्मदेव नारायण यादव]

शोषण के खिलाफ जो जंगल में बसने वाले आदिवासी, वनवासी हैं, वे भारत माता के बिनाही संतान बनकर खड़े हो गए हैं, उनसे निपटने के लिए, उनको अधिकार दिलाने के लिए सरकार एक आयोग की स्थापना करे, जो इन बातों को जांचे और जो उन इलाके में उनके उचित अधिकार हैं, उनको दिलाए और जो राष्ट्र-विरोधी तत्व हैं, उनसे सख्ती से निपटे। धन्यवाद।

श्री उपसभापति: श्री चतुरानन मिश्रा, माननीय सदस्य जरा संक्षेप में करें। वैसे सब बातें आ गई हैं...

श्री चतुरानन मिश्रा (बिहार): मान्यवर, जो समस्या अभी कॉल-अटेशन के जरिए लाई गई है, वह गंभीर तो जरूर है, लेकिन इतनी भयावह नहीं है कि अलग राष्ट्र वहां बन जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा। ऐसी स्थिति नहीं है। यह जरूर है कि वहां की सोशो-इकानोमी कंडीशन जो है, उसकी ओर सरकार का ध्यान नहीं जाता और इसलिए कुछ भी हो सकता है। मैं आपसे यहाँ कहना चाहता हूँ कि वहाँ 14 मिलियन टोटल आदमी रहते हैं उस पूरे छोटे नागपुर में, उस इलाका से मैं तीन बार असेम्बली में चुना गया हूँ और इसलिए मैं जानता हूँ। उस 14 लाख में से 1 लाख लोग अप्रूटेड हैं यानी 14 में से एक अप्रूटेड है। एक डी० बी० सी० कार्पोरेशन के चलते वहाँ के पाँच हजार घर पानी में डूब गए, 85 हजार एकड़ जमीन सदा के लिए पानी में डूब गई। लेकिन उससे कोई इंच मात्र भी फायदा नहीं हुआ। इधर जितना भी हटिया

बना, बाकारो हुआ, बड़े-बड़े प्लांट बने, हमको उनके लिए कोई भी प्राथमिकता नहीं दी। वे लोग अप्रूटेड हुए, भिन्न-भिन्न होकर भागे फिरे। लकड़ी का कुछ कंपनसेशन दिया गया, उनमें भी कुछ नहीं हो सका।

एक फारेस्ट एक्ट के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। उस फारेस्ट एक्ट के अंदर हमारे होम मिनिस्टर उस पर ध्यान करें। तो उसमें हर टेथ आदमी पर्सिड हो चुका है। टोटल पापुलेशन में दस आदमी में से एक आदमी राजा या चूका है। जो लोग जंगल काटने की बात करते हैं, तो यह कहना कठिन है कि टेकेंडरों ने ज्यादा जंगल बरबाद किए या इन आदिवासियों ने किए। मैं जंगल काटने के पक्ष में नहीं हूँ। लेकिन आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि टेकेंडरों ने जंगल को बरबाद कर दिया। सरकार ने क्या किया। हम होम मिनिस्टर से कहना चाहेंगे कि इन्होंने जो वक्तव्य पढ़ा, अधूरा वक्तव्य दिया। उस कोल्हन एरिया में 300 मकान जो आदिवासियों के थे, तोड़ दिए। अगर सरकार न करे, तो मैं चुनौती देता हूँ, मैं सदन से इस्तीफा दूंगा, अगर मेरी बात सच नहीं होगी। और जांचो नहीं जाएगी। तीन सौ घरों को तोड़ दिया है पुलिस ने। पुलिस गोली-कांड में मारे गये हैं सौ से ज्यादा लोग। एक बार में ही 35 आदमी मारे गए हैं चाइबासा में। मंत्री महोदया उन वक्त भी थे और जानते हैं प्रदास किया गया, उनमें 76 स्कीमें थीं। उसमें था कि प्राधिकार बनाया जाए। उस वक्त जो पायलेट कर रहे थे, हमारी राम दुलारी सिन्हा जी, जो कि हमारे बिहार से ही कैबिनेट सदस्य थी और बहुत इमपोर्टेंट सदस्या रही

है, इसलिए मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि वह प्राधिकार बना ही रह गया कायज पर। मैं भी उसका सदस्य था। हमने आदिवासियों की आकांक्षा के मुताबिक, उनकी अभिलाषा के मुताबिक उनकी जो पावर है, उसके मुताबिक प्रशासन नहीं देते हैं। हम जो यह बनाते हैं, बी० डी० ओ० वगैरह, यह सब इससे काम नहीं चलता है। यह समस्या नहीं है। हाईकोर्ट के जज के लिए, जज लोग हमारे ऐसे हैं और हमारे विधान ऐसे हैं, कोई आदमी हरिजन नहीं है, हर जगह आरक्षण के नियम लागू हैं, हाईकोर्ट में नहीं है। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि हमारी सेवा में, चाहे सेंटर में या दूसरी सरविसेज में आदिवासियों को स्थान नहीं मिला है।

यह प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि उन के विकास के अनुरूप प्रशासन नहीं मिलता। हम बाहरी तत्वों को भेज देते हैं और जैसा डेवलपमेंट एरिया में प्रशासन चलते हैं वैसा ही वहाँ भी चलाना चाहते हैं जिसका तर्जुमा होता है कि सौ रुपये अगर हम खर्च करते हैं तो उस में एक रुपया भी एक्जुथल आदमी के पास नहीं जा पाता है। यह सब से बड़ा दोष है।

कमीशन की बात आई। बिना कमीशन के भी किया जा सकता है। हम को ऐसा लगता है कि हमारे संविधान में इस मामले में सफाईकॉट प्रोवाइज नहीं है कि रोजनल आटोनामी दे सके। जब तक हम उनको अपने प्रशासन में एंसाइएट नहीं करेंगे, सम्पूर्ण भारत के अंग के रूप में उनका विकास नहीं करेंगे, उन के प्रति जो हमारी घनघोर उपेक्षा है, जो उनको सताने का काम है उस को अविलम्ब रोकेंगे नहीं तब तक इस समस्या का

निदान नहीं होगा। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूँगा—इस में राज्य सरकार तो बिल्कुल असफल हो गई है, मेरा अनुभव है, होम मिनिस्टर भी कह सकती है कि राज्य सरकार फेल हो गयी है—कि केन्द्रीय सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे ताकि जो हम फंडस देते हैं वे बढ़ाये जा सकें। रिप्रेसिव मैजर्स के जरिये इस समस्या का निदान नहीं होगा, बगावत होगी, अंग्रेजों के वक्त में बगावत हुई, हमारे वक्त में भी हुई। यह साल्यूशन नहीं है। इसलिए मैं अनुरोध करूँगा कि इस सम्बन्ध में अविलम्ब उचित जाँच की जाय, विरोध पक्ष को भी इस में शामिल किया जाय, उन आदिवासियों से भी सहयोग लिया जाय और इस का हम लोग निदान निकाल सकें। (समय की घंटी) मैं दो मिनट और समय लूँगा। उन के लिए सब से फायदे का काम होता हाइडेल प्रोजेक्ट कोइल-बारो का विकास। यह 700 करोड़ की योजना है। बिहार सरकार उस को नहीं कर सकी। उसने दिल्ली को दे दिया। दिल्ली की केन्द्रीय सरकार को चार वर्ष हो गये, उस ने भी नहीं किया। कोई प्रगति का काम किया ही नहीं जा सकता क्योंकि ऐसा दूषित वातावरण हो गया है अविश्वास का। इस लिए मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि वक्त रहते इस में हस्तक्षेप करे।

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY (Andhra Pradesh); Mr. Deputy Chairman, Sir> the statement...

SHRI J. K. JAIN (Madhya Pradesh): He is not concerned about his State. How is he concerned about... ?

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: I am concerned with the whole country. You are concerned with Delhi only

SHRI I. K. JAIN; What are you doing in Andhra Pradesh?

SHRIMATI RAM DULARI SINHA: Sir, I was all along listening to the criticisms and suggestions made by Shri Misra, Shri Goswami, Shri Bharadwaj, Shri Pradhan, Shri Chaturananji and Shri Reddy, I do not know from where I should start my reply _

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : मेरा नाम भूल गयीं आप ।

श्रीमती राव दुलारी सिन्हा : हुक्मदेव नारायण जी मेरे बड़े मित्र हैं । मैं उन की कद्र करती हूँ ।

Sir, I have already stated about their demands But I am surprised to listen from Mr. Reddy that he still wants to know what their demands were and he says that the Government is not seized of it He should know that the organisation is instigating tribals and demanding an independent Kolhan State. People who would not toe their line and support their demands are allegedly tortured or even liquidated.

The members Of the Sangh are mainly working in remote areas. They organise village meetings and incite innocent tribals to take up arms against the Government. They are also reported to have been imparting guerilla warfare training to young tribals

Sir, as regards the cutting of the trees. Mr Mishra has supplied a list to the Government. According to the reports received from the Government of India in 1980-81, the Kolhan Raksha Sangh started the agitation by felling forests in the Singhbhum District. Till February, 1984 the members of the Sangh were responsible for cutting valuable trees from an area of about 20,000 acres and taking forcible possession of about 10,000 acres of forest land

During the recent past. Sir, the Gram Raksha Dal, headed by one Shri Curia Gangra, has also become active in the Kolhan area. And it is said that the Dal is suspected to be an organisation of the Raksha Sangh. About that, I have

those of extremist type. They have launched an agitation of abducting and subsequently liquidating the adivasis who do not toe their line on the plea that they are criminals. On an enquiry, it transpired that many of those abducted and reportedly killed by them had no known past criminal history. The first case of this kind was reported in the first week of September, 1983 in Tonto Police Station in the Singhbhum District. It is suspected that Shri K. C. Hembrom and his associates were responsible for kidnapping 30 adivasis and subsequently killing them. So far 23 cases have come to the notice of the police, in which, I have already stated, 17 persons were killed and 49 were abducted whose whereabouts are not known. In some of the cases certain adivasi women were branded as *dayan*. They were kidnapped and subsequently murdered. As regards the help from the missionaries, there is a serious apprehension that they are getting the financial assistance from missionaries. It has been found that missionaries press had a hand in the publication brought out by this Sangh. There are proofs that the missionaries are giving financial assistance to them in fighting out cases filed against the Sangh leaders in the Courts. Sir the Government are vigilant about the activities of these organisations i.e., Kolhan area and have taken several measures to deal with the situation:—

(1) law and order enforcement machinery in the area has been suitably strengthened and reinforced.

(2) Sir, the important functionaries of the Sangh, as Mr. Hukmdeo Narayan Yadavji had enquired from me about the important functionaries of the Sangh, they have been identified and prosecution has been sanctioned against its 16 members for offence and sedition. Among them, Shri Christ Anand Topno and Shri Ashwini Kumar Sawaian were arrested on 26th October, 1981 and sent to jail. Subsequently, Shri Bishram Lakra, Superintendent G.E.L. Press Ranchi was also arrested and sent to jail. However, they have been released on bail under the orders of Patna High Court, Ranchi

-----it is for netition dated

[Shrimati Ram Dularj Sinha]

25-5-1984 and 29-5-1984 respectively.

Sir, steps are being taken to arrest the other accused persons.

(3) Sir, in order to prevent illegal felling of trees, army pickets with Magistrates have been deputed at 12 sensitive pockets as a result of which instances of illegal forest felling have decreased considerably.

(4) Sir, development activities have been intensifies in the area particularly for providing drinking water, education, medical and fair price shops facilities.

(5) Sir, local administration authorities have been suitably instructed to look into the grievances of the people and take necessary immediate steps for the redressal of the same.

(6) In view of the unrest prevailing in the Tribal areas, in the State of Bihar, the Prime Minister has observed that the matter of securing statutory representation of tribals in institutions functioning in the tribal areas in Bihar should be taken up

- with a sense of urgency. The Secretary, Ministry of Home Affairs has already requested the Chief Secretary to the Government of Bihar to initiate urgent action on this matter

(7) Sir, a Special Central Assistance, as I have already stated for the Tribal areas in the state of Bihar, has been increased from Rs. 15.66 crores in 1983-84 to Rs. 18.23 in 1984-85.

- (8) Sir, after a recent visit of the Joint Secretary, Tribal Development of the Ministry of Home Affairs of the area, j have specifically requested the State Government of Bihar to initiate action on dovetailing of the village office system of Mankis and Munda, into the existing Panchayati Raj system ^{an^} to energise enforcement of Land Alienation Legislation, cooperative enrolment, plantation of minor forest produce species, relevant to the tribal economy and eradication of bonded labour system in the area.

Sir, I have also decided to discuss the matters concerning tribal unrest with the Ministry of Tribal Development Government of Bihar and the Government of Bihar have been requested to furnish agenda notes on the topics to be discussed.

- As regards the suggestions by the hon. Members for the development of this area, it will be included in the agenda of my discussion with the concerned Minister of Bihar when he comes for discussion.

Sir, I would like to express my thanks to the hon. Members for their suggestions and criticisms during the debate.

Thank you.

श्री उप सभापति : सदन की कार्यवाही
2.25 बजे के लिए सदन की स्थिति की
जाती है

The House then adjourned for lunch at twenty-five minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at twenty-eight minutes past two of the clock.

Mr. Deputy Chairman in the Chair.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now we will take up special Mentions. Mr. V. Gopalsamy.

REFERENCE TO THE ATROCITIES REPORTEDLY BEING COMMITTED ON TAMIL SPEAKING PEOPLE IN SRI LANKA

SHRI V. GOPALSAMY (Tamil Nadu): Mr Deputy Chairman, Sir, I would like to draw the attention of the Government through you, to the continuous persecution of Tamils in Sri Lanka. Sir, since the 23rd of this month. Tamils all over the world have observed a one-week mourning for the terrible tragedy which took place during the month of July last year. Due to the blanket censorship in Sri Lanka, the atrocities committed against the Tamils there, particularly against the youths, do not come to tight. But the Tamils are attacked, particularly the youths, they are detained in cells and to elicit information, indescribable horrors are committed against them. Because of this, a heavy exodus has started since July last year and during my recent visit to Europe, I visited some of the camps in West Germany, Switzerland, Italy and also France where thousands of youth are stranded like international